DAINIK JAGRAN, Gorakhpur, 21.9.2023
Page No. 15, Size:(5.37)cms X (8.51)cms.

# महिला आरक्षण बिल लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी क्रांति : मुर्मु

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय में सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

राष्ट्रपति विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।

सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को इसी तरह का आरक्षण देने का प्रस्ताव अब ठोस रूप ले रहा है।' इस सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 सितंबर को एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लोगों से मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर नहीं देखने का आग्रह किया और पर्यावरण की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ● एएनआइ

देखभाल पर भी समान रूप से ध्यान देने को कहा। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि मनुष्यों की नासमझी से प्रकृति को गहरा नुकसान हुआ है। मुर्मु ने कहा, 'मनुष्य जितना अच्छा निर्माता है, उतना ही विध्वंसक भी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, यह पृथ्वी छठे विलुप्ति के चरण में प्रवेश कर चुकी है जिसमें अगर मानव निर्मित विनाश को नहीं रोका गया तो न सिर्फ मानव जाति का, बल्कि पृथ्वी पर अन्य जीवों का भी विनाश हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर न देखें।'

VOICE OF LUCKNOW, Lucknow, 21.9.2023
Page No. 12, Size:(0)cms X (0)cms.

# महिला आरक्षण बिल सबसे परिवर्तन कारी क्रांति : मुर्मू

एजेंसी

नयी दिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पेश किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को कहा कि यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगा। मुर्मू यहां विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थी।

महिला आरक्षण विधेयक नये संसद भवन में मंगलवार को पेश किया गया पहला विधेयक था। राष्ट्रपति ने कहा, हमने स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है। एक और सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और देश की संसद में महिलाओं के लिए ऐसा ही आरक्षण देने वाला एक प्रस्ताव अब आगे बढ़ रहा है। यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) 20-21 सितंबर को एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है।

इसमें भारत और विदेश के 1,300 से अधिक प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की सचिव अमीना बोयाच, एपीएफ की अध्यक्ष डू-हयान सोंग और

एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायधीश (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्र भी इस मौके पर उपस्थित रहे। एनएचआरसी ने पहले बताया था कि एपीएफ सदस्य देशों के साझा हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुधवार को 28वीं वार्षिक आम बैठक भी करेगा। सम्मेलन में देश में मानवाधिकारों की रक्षा में शामिल केंद्र तथा राज्य सरकारों, राज्य मानवाधिकार आयोगों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न देशों के एनएचआरआई के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने बुधवार को मानवाधिकार को एक अलग मुद्दा न मानने का आग्रह करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण की देखभाल पर समान ध्यान देने पर जोर दिया और इस बात पर अफसोस जताया कि मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों से मातृ प्रकृति बुरी तरह से आहत है। विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुर्मू ने यह भी कहा कि इससे पहले कि बहुत देर हो जाएं प्रकृति के संरक्षण और समृद्धि के लिए इसके (प्रकृति के) प्रति प्रेम को फिर से जागृत किया जाना चाहिए। कार्यक्रम का आयोजन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) के सहयोग से 20-21 सितंबर को किया जा रहा है।

मुर्मू ने कहा कि उन्होंने मंच के पहले हुए सम्मेलनों की सूची देखी और इस बात पर खुशी जताई की कोविड के बाद भौतिक रूप से आयोजित यह पहला सम्मेलन है। उन्होंने कहा, मुझे बताया गया है कि सम्मेलन में करीब 100 विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। मुर्मू ने प्राकृतिक पर्यावरण में आ रही गिरावट को भी रेखांकित किया। राष्ट्रपति ने कहा, मानव जितना अच्छा निर्माता है उतना ही विध्वंसक भी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, यह ग्रह विलुप्त होने के छठे चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसमें मानव निर्मित विनाश को अगर रोका नहीं गया। तो न केवल मानव जाति, बल्कि इस पृथ्वी पर अन्य जीवन भी नष्ट हो जाएगा।

JANSATTA, Chandigarh, 21.9.2023
Page No. 11, Size:(7.33)cms X (6.42)cms.

# राष्ट्रपति ने मानवाधिकारों के पोषण में मातृत्व स्वभाव अपनाने पर दिया जोर

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 सितंबर।

राष्ट्रपति दौपदी मुर्मू ने अपील की है कि मानवाधिकारों के मुद्दे को पृथक तौर पर नहीं लिया जाना चाहिए। इसके मातृत्व स्वभाव का पोषण करने पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है। यह प्रकृति लोगों की अविवेकपूर्ण हरकतों से बुरी तरह जख्मी है।

मानवाधिकार संस्थाओं के एशिया प्रशांत फोरम की वार्षिक बैठक और दो दिन के सम्मेलन का उदघाटन करते हुए राष्ट्रपति ने बुधवार को याद दिलाया कि भारत में मान्यता है कि सृष्टि का हर तत्व दैवीय चमत्कार है। फोरम में आए अनेक देशों के मानवाधिकार संगठनों के प्रतिनिधियों से राष्ट्रपति ने और देर किए बिना प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए अपना लगाव बढ़ाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मनुष्य जहां अच्छा सृजक होता है वहीं वह विध्वंस भी करता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार अब सृष्टि ऐसी स्थिति में पहुंच चुकी है कि मानवीय विध्वंस को रोका न गया तो धरती से मनुष्य ही नहीं अन्य जीवों का भी खात्मा हो जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि लिखित कानूनों से कहीं ज्यादा तो अंतराष्ट्रीय समुदाय का यह नैतिक दायित्व है कि मानवाधिकारों को हर नजरिए से सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि सम्मेलन का एक सत्र पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के विषय के लिए ही केंद्रीत है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सम्मेलन ऐसी सम्यक घोषणा करेगा जिससे ब्रह्माण्ड और मानवता दोनों की बेहतरी का मार्ग प्रशस्त होगा।

जनसत्ता Thu, 21 September 2023
https://epaper.jansatta.com/c/73499478

# President Murmu inaugurates conference of National Human Rights Institutions of Asia Pacific

https://www.aninews.in/news/national/general-news/president-murmu-inaugurates-conference-of-national-human-rights-institutions-of-asia-pacific20230920172349/

New Delhi [India], September 20 (ANI): President Droupadi Murmu on Wednesday inaugurated the two-day conference of the National Human Rights Institutions (NHRIs) of Asia Pacific organized by the National Human Rights Commission, NHRC, India, in collaboration with the Asia Pacific Forum at Vigyan Bhawan, New Delhi.
President Murmu said, "India and other nations of the Asia Pacific are civilizational protectors of human rights and can play a role in evolving an international consensus on related issues,"

Drawing attention to the issue of climate change impacting human rights, she exhorted to conserve and enrich nature before it is too late.
The President said "India has a long historical experience of practising and cherishing democratic values and individual rights. It adopted universal adult franchise rights since the inception of the republic. We ensured a minimum 33% reservation for women in local bodies and a proposal is taking shape to have the same in assemblies and parliament."

Earlier in his key note address, the NHRC, India, Chairperson Justice Arun Mishra said that the NHRIs of the Asia Pacific need a joint strategy for the emerging challenges to Human Rights protection in areas of climate change, child trafficking, Child Sexual Abuse Material (CSAM) and other crimes in cyberspace, the latest developments in Artificial Intelligence, among others.

Arun Mishra said that the concentration of wealth in a few hands globally is causing a brooding sense of injustice. We must ensure that workers involved in various economic activities are provided humane working conditions. Hesaid that business houses must be responsible for processing waste and removing debris from their premises. He said that in the matter of essential health issues, the intellectual property right, must adopt a right-based approach in essential health services in public interest.
He also strongly pitched in for ensuring gender justice for women and the LGBTQI community besides liberalising the concept of reasonable opportunity for the specially-abled.
On the occasion, Amina Bouayach, Secretary, Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) said "The world community recognizes the critical role of the NHRIs in promoting and protecting human rights. Their role has gained more significance in the contemporary times facing challenges of poverty, discrimination, shrinking civic space among other challenges,"
Doo-Hwan Song, Chairperson, Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions also addressed the gathering.

Prior to this, welcoming the dignitaries, Bharat Lal, Secretary General, NHRC, gave an outline of the scheduled discussions in various sessions of the two-day conference of the NHRIs of the Asia Pacific.

Bharat Lal said that the conference will provide an opportunity to deliberate upon various emerging challenges and find ways to promote and protect human rights.

"The conference including the Annual General Meeting (AGM) on 20th September, 2023 followed by the Biennial Conference will celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) and 30 years of National Human Rights Institutions and the Paris Principles, with a sub-theme on the environment and climate change. It is being attended by Heads, members, and senior officials of the NHRIs of the Asia Pacific region, observer countries along with representatives from the Union and State governments, State Human Rights Commissions, Special Rapporteurs, Monitors, various institutions involved in the protection and promotion of human rights in the country, members of civil society and NGOs, human right defenders, lawyers, jurists, academicians, diplomats, representatives of international organizations, and academic institutions," read the NHRC press release.

NHRC is also hosting an international seminar on ‘Business and Human rights’ for the development of strategies to ensure that businesses prioritize human rights and environmental sustainability in their operations.(ANI)

DAINIK JAGRAN, Varanasi, 21.9.2023
Page No. 13, Size:(5.11)cms X (7.70)cms.

# महिला आरक्षण बिल लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी क्रांति : मुर्मु

**नई दिल्ली, प्रेट :** राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय में सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

राष्ट्रपति विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।

सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को इसी तरह का आरक्षण देने का प्रस्ताव अब ठोस रूप ले रहा है।' इस सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 सितंबर को एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लोगों से मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर नहीं देखने का आग्रह किया और पर्यावरण की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ● एएनआइ

देखभाल पर भी समान रूप से ध्यान देने को कहा। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि मनुष्यों की नासमझी से प्रकृति को गहरा नुकसान हुआ है। मुर्मु ने कहा, 'मनुष्य जितना अच्छा निर्माता है, उतना ही विध्वंसक भी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, यह पृथ्वी छठे विलुप्ति के चरण में प्रवेश कर चुकी है जिसमें अगर मानव निर्मित विनाश को नहीं रोका गया तो न सिर्फ मानव जाति का, बल्कि पृथ्वी पर अन्य जीवों का भी विनाश हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर न देखें।'

JANSATTA, Delhi, 21.9.2023
Page No. 10, Size:(3.49)cms X (11.15)cms.

# 'महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 सितंबर।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 फीसद आरक्षण देने वाला विधेयक पेश किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को कहा कि यह लैंगिक न्याय के लिए 'हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगा।'

मुर्मू विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थीं। राष्ट्रपति ने कहा कि हमने स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 फीसद आरक्षण सुनिश्चित किया है, एक और सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और देश की संसद में महिलाओं के लिए ऐसा ही आरक्षण देने वाला एक प्रस्ताव अब आगे बढ़ रहा है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) 20-21 सितंबर को एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें भारत और विदेश के 1,300 से अधिक प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की सचिव अमीना बोयाच, एपीएफ की अध्यक्ष डू-ह्वान सोंग,एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायधीश (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा रहे।

जनसत्ता Thu, 21 Sept https://epap

# महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति : मुर्मू

https://hindi.theprint.in/india/womens-reservation-bill-is-the-most-transformative-revolution-of-our-times-for-gender-justice-murmu/602380/

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने वाला विधेयक पेश किए जाने के एक दिन बाद बुधवार को कहा कि यह लैंगिक न्याय के लिए ‘‘हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगा।’’

मुर्मू यहां विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित कर रही थीं।

महिला आरक्षण विधेयक नये संसद भवन में मंगलवार को पेश किया गया पहला विधेयक था।

राष्ट्रपति ने कहा, ‘‘हमने स्थानीय निकाय के चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है... एक और सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और देश की संसद में महिलाओं के लिए ऐसा ही आरक्षण देने वाला एक प्रस्ताव अब आगे बढ़ रहा है। यह लैंगिक न्याय के लिए हमारे दौर की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगा।’’

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) 20-21 सितंबर को एशिया पैसिफिक फोरम (एपीएफ) के साथ मिलकर इस सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें भारत और विदेश के 1,300 से अधिक प्रतिनिधियों के हिस्सा लेने की संभावना है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के वैश्विक गठबंधन की सचिव अमीना बोयाच, एपीएफ की अध्यक्ष डू-ह्वान सोंग और एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायधीश (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा भी इस मौके पर उपस्थित रहे।

एनएचआरसी ने पहले बताया था कि एपीएफ सदस्य देशों के साझा हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बुधवार को 28वीं वार्षिक आम बैठक भी करेगा।

सम्मेलन में देश में मानवाधिकारों की रक्षा में शामिल केंद्र तथा राज्य सरकारों, राज्य मानवाधिकार आयोगों और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों के साथ ही विभिन्न देशों के एनएचआरआई के वरिष्ठ अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं।

भाषा गोला पारुल

पारुल

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

# मानवाधिकार को अलग मुद्दा न माने, 'आहत' मातृ प्रकृति पर समान ध्यान दें: राष्ट्रपति

https://hindi.theprint.in/india/dont-consider-human-rights-as-a-separate-issue-pay-equal-attention-to-hurt-mother-nature-president/602517/

नयी दिल्ली, 20 सितंबर (भाषा) राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने बुधवार को मनावाधिकार को एक अलग मुद्दा न मानने का आग्रह करते हुए प्राकृतिक पर्यावरण की देखभाल पर 'समान ध्यान' देने पर जोर दिया और इस बात पर अफसोस जताया कि मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों से मातृ प्रकृति बुरी तरह से आहत है।

विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुर्मू ने यह भी कहा कि 'इससे पहले कि बहुत देर हो जाए' प्रकृति के संरक्षण और समृद्धि के लिए इसके (प्रकृति के) प्रति प्रेम को फिर से जागृत किया जाना चाहिए।

कार्यक्रम का आयोजन भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) एशिया प्रशांत मंच (एपीएफ) के सहयोग से 20-21 सितंबर को किया जा रहा है।

मुर्मू ने कहा कि उन्होंने मंच के पहले हुए सम्मेलनों की सूची देखी और इस बात पर खुशी जताई की कोविड के बाद भौतिक रूप से आयोजित यह पहला सम्मेलन है।

उन्होंने कहा, " मुझे बताया गया है कि सम्मेलन में करीब 100 विदेशी प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।"

मुर्मू ने प्राकृतिक पर्यावरण में आ रही गिरावट को भी रेखांकित किया।

राष्ट्रपति ने कहा, " मानव जितना अच्छा निर्माता है उतना ही विध्वंसक भी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, यह ग्रह विलुप्त होने के छठे चरण में प्रवेश कर चुका है, जिसमें मानव निर्मित विनाश को अगर रोका नहीं गया, तो न केवल मानव जाति, बल्कि इस पृथ्वी पर अन्य जीवन भी नष्ट हो जाएगा।"

उन्होंने कहा, " इस संदर्भ में, मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग न माने और मातृ प्रकृति की देखभाल पर भी समान ध्यान दें, जो मानव के अविवेकपूर्ण कार्यों से बुरी तरह से आहत है।"

राष्ट्रपति ने कहा, " भारत में हम यह मानते हैं कि ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दिव्यता की अभिव्यक्ति है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें प्रकृति के संरक्षण और समृद्धि के लिए अपने प्रेम को फिर से जगाना चाहिए।"

ग्लोबल अलांयस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रीयूशन की सचिव अमीना बौयाच, एपीएफ के अध्यक्ष डू-ह्वान सॉन्ग और एनएचआरसी के प्रमुख न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरूण कुमार मिश्रा ने राष्ट्रपति के साथ मंच साझा किया।

एपीएफ बुधवार को विज्ञान भवन में अपनी 28वीं वार्षिक आम बैठक भी आयोजित कर रहा है जिसमें सदस्य देशों के साझा हित के मुद्दों पर चर्चा की जा रही है।

सम्मेलन में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपीन, जॉर्डन और ऑस्ट्रेलिया सहित अन्य देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं।

मुर्मू ने कहा, " हमें एक पल के लिए अपने चारों ओर महामारी और प्राकृतिक आपदाओं के कारणों पर विचार करना चाहिए। हमें जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों पर भी विचार करना चाहिए जो पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में डाल रही हैं।'

राष्ट्रपति ने कहा, "मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा के मसौदे को आकार देने में (महात्मा) गांधी का जीवन और विचार भी महत्वपूर्ण थे। उन्होंने मानवाधिकार विमर्श को प्रभावित किया।"

मुर्मू ने कहा कि गांधीजी के प्रभाव की वजह से ही मानव अधिकारों की धारणा का विस्तार हुआ और यह जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं से लेकर जीवन की गरिमा तक विस्तारित हुआ।

उन्होंने कहा कि इसी तरह, डॉ. बीआर आंबेडकर मानवाधिकारों के प्रबल समर्थक थे। राष्ट्रपति के मुताबिक, डॉ आंबेडकर ने कमजोर वर्गों को अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना और सम्मान के साथ जीना सिखाया।

भाषा नोमान पवनेश

पवनेश

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

INDIAN EXPRESS, Delhi, 21.9.2023
Page No. 10, Size:(6.64)cms X (18.38)cms.

# Murmu: Women quota Bill is most 'transformative revolution'

**PRESS TRUST OF INDIA**
NEW DELHI, SEPTEMBER 20

PRESIDENT DROUPADI Murmu on Wednesday said the women's reservation Bill will be the most "transformative revolution in our times" for gender justice.

Murmu was addressing a gathering after inaugurating the biennial conference of the national human rights institutions (NHRIs) of Asia Pacific held at the Vigyan Bhawan here.

"We have ensured a minimum of 33 per cent reservation for women in local bodies' election... In a more pleasant coincidence, a proposal to provide a similar reservation for women in state assemblies and national Parliament is taking shape now. It will be the most transformative revolution in our times for gender justice," the President said.

# President Droupadi Murmu inaugurates conference of National Human Rights Institutions of Asia Pacific Region

https://www.indialegallive.com/top-news-of-the-day/news/president-droupadi-murmu-inaugurate-conference-national-human-rights-institutions-asia-pacific-region/

President Droupadi Murmu on Wednesday inaugurated the two-day conference of National Human Rights Institutions of the Asia Pacific Region at the Plenary Hall of Vigyan Bhawan, New Delhi.

The President said on the occasion that the subject of human rights has always been very close to her heart.

She applauded the National Human Rights Commission (NHRC), India and the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions for organising the event and said that such conferences should be held on a regular basis for the betterment of all.

Expressing her happiness over the introduction of the Women's Reservation Bill in the Lok Sabha on Tuesday, she said it was the right step in the right direction, which would pave the way for the empowerment of women.

The inaugural session of the National Human Rights Institutions of the Asia Pacific region conference kickstarted at 11:00 am with the Annual General Meeting (AGM), 2023.

At 12:30, a seminar was held by NHRC, India on 'Business and Human Rights'. The seminar was divided into two thematic sessions – 'Harmonising climate change, human rights and business,' and 'Advancing human rights in business and industry.'

A Biennial Conference will be held tomorrow as part of the event, to celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) and 30 years of National Human Rights Institutions and the Paris Principles, with a sub-theme on the environment and climate change.

The event is expected to serve as a platform for meaningful discussions, knowledge sharing and the development of strategies to ensure that businesses prioritise human rights and environmental sustainability in their operations.

Keynote speakers and panellists include prominent figures from the human rights paraphernalia, senior government functionaries, environmental, and corporate experts and regulators with diverse perspectives and insights.

Attendees will also have the opportunity to engage in interactive sessions and network with like-minded individuals and organisations committed to advancing the cause of human rights in business. All sessions of the conference will be streamed live through webcast.

AAJ, Patna, 21.9.2023
Page No. 01, Size:(12.87)cms X (10.31)cms.

# महिला आरक्षण बिल के समर्थन में राष्ट्रपति

**नयी दिल्ली** (एजेंसी)। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने दिल्ली में एशिया प्रशांत फोरम की 28वीं वार्षिक आम बैठक और द्विवार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। नये संसद भवन में महिला आरक्षण विधेयक पर राष्ट्रपति मुर्मु ने भी बयान दिया। उन्होंने इसका पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि लैंगिक न्याय के लिए यह हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

राष्ट्रपति मुर्मु ने कहा कि हमने स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 फीसदी आरक्षण सुनिश्चित किया है। राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय संसद में महिलाओं के लिए समान आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव अब आकार ले रहा है, जो कि हमारे समय की सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी। बता दें कि महिला आरक्षण बिल मंगलवार को नए संसद भवन में पेश किया जाने वाला पहला बिल था। आज इस बिल को लेकर सदन में बहसा-बहसी चल रही है।

बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु जिस बैठक में शामिल हुई है, वह 20 से 21 सितंबर तक चलेगा। इसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से 20-21 सितंबर तक आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस की सचिव अमीना बौयाच और एपीएफ के अध्यक्ष डू-ह्वान सॉन्ग और एनएचआरसी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा भी उपस्थित थे।

सम्मेलन में विभिन्न देशों के

( शेष पृष्ठ ९ पर )

## महिला आरक्षण बिल...

किया। गुरुवार को इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। वहां से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साइन के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा। महिला आरक्षण बिल नई संसद के लोकसभा में पास हुआ पहला बिल है।

महिला आरक्षण बिल के मुताबिक, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए ३३ प्रतिशत आरक्षण १५ साल तक के लिए लागू किया जाएगा। इसके बाद संसद चाहे तो इसकी अवधि बढ़ा सकती है। लोकसभा की ५४३ सीटों में से १८१ महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। यह आरक्षण सीधे चुने जाने वाले जनप्रति. निधियों के लिए लागू होगा। यानी यह राज्यसभा और राज्यों की विधान परिषदों पर लागू नहीं होगा।

इससे पहले सरकार तरफ से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर सरकार का पक्ष प्रस्तुत करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि महिला सशक्तिकरण कुछ पार्टियों के लिए राजनीधतिक एजेंडा हो सकता है। भाजपा के लिए यह मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि कल का दिन भारतीय संसद के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कल के दिन वर्षों से जो लंबित था वो महिलाओं को अधिकार देने का बिल सदन में पेश हुआ। इसके लिए गश्हमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद दिया।

शाह ने कहा कि कुछ पार्टियों के लिए महिला सशक्तिकरण एक राजनीतिक एजेंडा और चुनाव जीतने का राजनीतिक उपकरण हो सकता है, लेकिन भाजपा और नरेंद्र मोदी के लिए यह कोई राजनी. तिक मुद्दा नहीं है। अलबत्ता, यह मान्यता का सवाल है। उन्होंने कहा कि इस बिल के पारित होने से महिलाओं के अधिकारों की लंबी लड़ाई खत्म हो जाएगी। जी २० के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने महिला नेतृत्व वाले विकास का विजन पूरी दुनिया के सामने रखा। उन्होंने संकेत दिया कि संसद से पास होने के बाद यह विधेयक २०२९ के बाद अमल में आएगा। उन्होंने कहा कि यह युग बदलने वाला विधेयक है।

शाह ने कहा कि कोई जवाब को अपने दिल से न लगा ले। एक ऐसा मौका है, जिसमें समग्र देश और समग्र विश्व को यह संदेश देने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। यह पांचवां प्रयास है। यह विधेयक पहली बार नहीं आया है। यह संविधान संशोधन विधेयक पहली बार नहीं आया। क्यों मोदी जी को यह विधेयक लाना पड़ा? किसके कारण पारित नहीं हो सका था? क्या प्रयास अधूरे थे, मंशा अधूरी थी?

गृहमंत्री ने कहा कि सबसे पहले १९९६ में यह विधेयक देवेगौड़ा के कार्यकाल में आया। इसका श्रेय कांग्रेस को देना हो तो दे दीजिए। तब कांग्रेस विपक्ष में थी। विधेयक को सदन में रखने के बाद संयुक्त समिति को दे दिया गया। नौ दिसंबर १९९६ को समिति ने रिपोर्ट दे दी, लेकिन विधेयक सदन में पारित नहीं हो सका। जब ११वीं लोकसभा भंग हो गई तो विधेयक विलोपित हो गया। अधीर रंजन ने कहा कि विधेयक लंबित है, हमारा ही विधेयक रखा हुआ है, जबकि विधेयक लंबित नहीं था, जिंदा नहीं था। जब लोकसभा भंग हो जाती है तो अनुच्छेद १०७ के तहत लंबित विधेयक विलोपित हो जाते हैं। ये मुझसे दस साल का हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन अपने साठ साल का हिसाब नहीं देते। यह विधेयक चार बार आया, पारित नहीं हुआ। हर बार इस देश की मातृशक्ति को इस सदन ने निराश किया। हमारी मंशा पर सवाल उठाए गए।

अमित शाह ने कहा कि ओबीसी आरक्षण, परिसीमन का मुद्दा या जनगणना को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। संविधान के तहत में तीन तरह के सांसद आते हैं, जो सामान्य, एससी और एसटी श्रेणी से आते हैं। इन तीनों श्रेणियों में हमने महिलाओं का ३३ प्रतिशत आरक्षण कर दिया है। अब एक तिहाई सीटों को आरक्षित करना है तो वह सीट कौन तय करेगा? हम करें? अगर वायनाड आरक्षित हो गया तो आप कहेंगे हमने राजनीति की है। शाह ने कहा कि सोशल मीडिया पर कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बिल का समर्थन नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें ओबीसी, मुसलमानों का आरक्षण नहीं है। अगर आप इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो क्या आरक्षण जल्दी होगा? अगर आप इस बिल का समर्थन करते हैं तो कम से कम गारंटी तो देंगे।

DAINIK JAGRAN, Delhi, 21.9.2023
Page No. 2, Size:(30.29)cms X (14.62)cms.

# महिला आरक्षण बिल लैंगिक न्याय के लिए परिवर्तनकारी क्रांति : मुर्मु

नई दिल्ली, प्रेट्र: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय में सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

राष्ट्रपति विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है। सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को इसी तरह का आरक्षण देने का प्रस्ताव अब ठोस रूप ले रहा है।' इस सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 सितंबर को एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से

नई दिल्ली में एशिया प्रशांत फोरम के द्विवार्षिक सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा●एएनआइ

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लोगों से मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर नहीं देखने का आग्रह किया और पर्यावरण की देखभाल पर भी समान रूप से ध्यान देने को कहा। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि मनुष्यों की नासमझी से प्रकृति को गहरा नुकसान हुआ है। मुर्मु ने कहा, 'मनुष्य जितना अच्छा निर्माता है, उतना ही विध्वंसक भी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, यह पृथ्वी छठे विलुप्ति के चरण में प्रवेश कर चुकी है जिसमें अगर मानव निर्मित विनाश को नहीं रोका गया तो न सिर्फ मानव जाति का, बल्कि पृथ्वी पर अन्य जीवों का भी विनाश हो जाएगा। मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर न देखें।' राष्ट्रपति ने कहा, 'भारत में हम मानते हैं कि ब्रह्मांड के प्रत्येक कण में भगवान का वास होता है। इससे पहले कि देर हो जाए, आइए प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए इसके प्रति प्रेम को फिर से जागृत करें।' राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और एशिया प्रशांत के अन्य देश मानवाधिकारों के सभ्यतागत संरक्षक हैं और संबंधित मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति विकसित करने में भूमिका निभा सकते हैं। सम्मेलन में नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिलीपींस, जार्डन, आस्ट्रेलिया और अन्य देशों के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

## व्यवसायों को जवाबदेह होना होगा : जस्टिस मिश्रा

एनएचआरसी के चेयरपर्सन जस्टिस (सेवानिवृत्त) अरुण मिश्रा ने इस अवसर पर कहा कि खतरनाक व्यवसायिक गतिविधियों में शामिल होने पर बड़े व्यवसायों को मानवाधिकारों के प्रति जवाबदेह होना होगा। उन्होंने कहा, '1984 में भोपाल में सबसे भीषण गैस त्रासदी के बाद खतरनाक मलबा अभी भी हटाए जाने की प्रतीक्षा में है। इस देरी से भूजल और मिट्टी प्रदूषित हो रही है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कड़े सुरक्षा उपाय और दायित्व आवश्यक हैं। कहा, 'हमें आतंकवाद, नशीली दवाओं के दुरुपयोग व युद्ध पीड़ितों के मानवाधिकारों और जीवन, आजीविका व शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व पर उनके प्रभाव की रक्षा करनी है।'

INDIAN EXPRESS, Ahmedabad, 21.9.2023
Page No. 16, Size:(5.34)cms X (13.68)cms.

# India, other Asia-Pacific nations civilisational protectors of human rights, says President

**President Droupadi Murmu being felicitated by NHRC chairperson Justice Arun Kumar Mishra during the opening of a two-day conference in New Delhi on Wednesday.** *PTI*

**EXPRESS NEWS SERVICE**
NEW DELHI, SEPTEMBER 20

PRESIDENT DROUPADI Murmu Wednesday said that India and other Asia-Pacific nations were civilisational protectors of human rights who could play a role in attaining a consensus on international issues.

Murmu was speaking after inaugurating the two-day conference organised the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan.

The conference of the National Human Rights Institutions (NHRIs) was organised in collaboration with the Asia Pacific Forum.

Murmu further mentioned India adopted a universal adult franchise right after gaining independence.

Among other speakers were NHRC chairperson Justice Arun Mishra, Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) secretary Amina Bouayach and Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions Chairperson Mr Doo-Hwan Song.

In the keynote address, Mishra spoke of the need for NHRIs of the Asia-Pacific to formulate a joint strategy to solve challenges in areas of climate change, child trafficking, Child Sexual Abuse Material (CSAM) and other crimes in cyberspace, the latest developments in Artificial Intelligence, among others.

He also spoke about the concentration of global wealth in a few hands.

Misra further pitched for a rights-based approach to be adopted in matters of essential health issues, and intellectual property rights. He also spoke about ensuring gender justice for women and LGBTQI community.

On the other hand, Bouayach said NHRIs were critical for promoting and protecting human rights in challenging times of poverty, discrimination and shrinking civic space.

# Prez Droupadi Murmu addresses the conference of National Human Rights Institutions of Asia Pacific region in New Delhi

https://newsonair.com/2023/09/20/prez-droupadi-murmu-addresses-the-conference-of-national-human-rights-institutions-of-asia-pacific-region-in-new-delhi/

President Droupadi Murmu today said that the Indian Constitution has enabled numerous silent revolutions, in the field of gender justice, and protection of life and dignity since its inception. Addressing the conference of National Human Rights Institutions of the Asia Pacific region in New Delhi, the President said that over the years, the government has also launched a number of ambitious schemes to ensure basic facilities like housing, toilets, education, and health facilities and thus protect the dignity of the poor.

The President said that India has ensured a minimum of 33 percent reservation for women in local bodies elections. She added that similar reservation for women in the state assemblies and national Parliament is taking shape now. The President said that it will be the most transformative revolution in our times for gender justice

President Murmu stressed that Mahatma Gandhi's life and thoughts gave a path to shaping the Universal Declaration for Human Rights. She said that Mahatma Gandhi inspired many lives about the discrimination and fight against dignity after an incident in South Africa during a train journey. Highlighting the contribution of Dr. Bhim Rao Ambedkar, the President said, Dr. B R Ambedkar was an advent champion of Human Rights, who taught the depressed classes to stand up for their rights and live with dignity.

Akashwani correspondent reports that the two-day conference will celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights and 30 years of National Human Rights Institutions and the Paris Principles. It will also hold a sub-theme on the environment and climate change. Additionally, the National Human Rights Commission, India will also organise a seminar on Business and Human Rights. The event aims to ensure that businesses prioritize human rights and environmental sustainability in their operations.

# राष्ट्रपति मुर्मू ने एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के सम्मेलन का उद्घाटन किया

https://jantaserishta.com/delhi-ncr/president-murmu-inaugurates-conference-of-national-human-rights-institutions-of-asia-pacific-2829643?infinitescroll=1

नई दिल्ली (एएनआई): राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एनएचआरसी, भारत के सहयोग से एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों (एनएचआरआई) के दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एशिया प्रशांत मंच।

राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, "भारत और एशिया प्रशांत के अन्य देश मानवाधिकारों के सभ्यतागत संरक्षक हैं और संबंधित मुद्दों पर अंतरराष्ट्रीय सहमति विकसित करने में भूमिका निभा सकते हैं।"

मानवाधिकारों पर असर डालने वाले जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करते हुए उन्होंने बहुत देर होने से पहले प्रकृति के संरक्षण और संवर्धन का आह्वान किया।

राष्ट्रपति ने कहा, "भारत के पास लोकतांत्रिक मूल्यों और व्यक्तिगत अधिकारों का अभ्यास करने और उन्हें संजोने का एक लंबा ऐतिहासिक अनुभव है। इसने गणतंत्र की स्थापना के बाद से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अधिकारों को अपनाया। हमने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33% आरक्षण सुनिश्चित किया है और एक प्रस्ताव लाया जा रहा है।" विधानसभाओं और संसद में भी ऐसा ही होगा।"

इससे पहले अपने मुख्य भाषण में, एनएचआरसी, भारत के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि एशिया प्रशांत के एनएचआरआई को जलवायु परिवर्तन, बाल तस्करी, बाल यौन शोषण सामग्री के क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण के लिए उभरती चुनौतियों के लिए एक संयुक्त रणनीति की आवश्यकता है। सीएसएएम) और साइबरस्पेस में अन्य अपराध, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में नवीनतम विकास, अन्य।

अरुण मिश्रा ने कहा कि विश्व स्तर पर धन का कुछ ही हाथों में केन्द्रित होना अन्याय की भावना को जन्म दे रहा है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल श्रमिकों को मानवीय कार्य परिस्थितियाँ प्रदान की जाएँ। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक घरानों को कचरे के प्रसंस्करण और अपने परिसर से मलबा हटाने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों, बौद्धिक संपदा अधिकार, जनहित में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं में अधिकार आधारित दृष्टिकोण अपनाना होगा।

उन्होंने विशेष रूप से विकलांगों के लिए उचित अवसर की अवधारणा को उदार बनाने के अलावा महिलाओं और एलजीबीटीक्यूआई समुदाय के लिए लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने की भी जोरदार वकालत की।

इस अवसर पर, ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन (जीएएनएचआरआई) की सचिव अमीना बौयाच ने कहा, "विश्व समुदाय मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में एनएचआरआई की महत्वपूर्ण भूमिका को पहचानता है। समकालीन समय में चुनौतियों का सामना करने में उनकी भूमिका को और अधिक महत्व मिला है।" अन्य चुनौतियों के बीच गरीबी, भेदभाव, सिकुड़ता नागरिक स्थान,"

राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया प्रशांत मंच के अध्यक्ष डू-ह्वान सॉन्ग ने भी सभा को संबोधित किया।

इससे पहले, गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए, एनएचआरसी के महासचिव भरत लाल ने एशिया प्रशांत के एनएचआरआई के दो दिवसीय सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में निर्धारित चर्चा की रूपरेखा दी।

भरत लाल ने कहा कि सम्मेलन विभिन्न उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करने और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के तरीके खोजने का अवसर प्रदान करेगा।

“20 सितंबर, 2023 को वार्षिक आम बैठक (एजीएम) सहित सम्मेलन, जिसके बाद द्विवार्षिक सम्मेलन होगा, मानव अधिकारों पर सार्वभौम घोषणा (यूडीएचआर) की 75 वीं वर्षगांठ और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और पेरिस सिद्धांतों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाएगा। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर एक उप-विषय। इसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के एनएचआरआई के प्रमुख, सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, पर्यवेक्षक देशों के साथ-साथ संघ और राज्य सरकारों, राज्य मानवाधिकार आयोगों, विशेष के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। रिपोर्टर्स, मॉनिटर्स, देश में मानवाधिकारों की सुरक्षा और प्रचार में शामिल विभिन्न संस्थान, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, मानवाधिकार रक्षक, वकील, न्यायविद, शिक्षाविद, राजनयिक, अंतरराष्ट्रीय संगठनों और शैक्षणिक संस्थानों के प्रतिनिधि, "पढ़ें। एनएचआरसी प्रेस विज्ञप्ति.

एनएचआरसी रणनीतियों के विकास के लिए 'व्यापार और मानवाधिकार' पर एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार की भी मेजबानी कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यवसाय अपने संचालन में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता दें। (एएनआई)

# India, other Asia-Pacific nations civilisational protectors of human rights, says President

Murmu was speaking after inaugurating the two-day conference organised the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan.

https://indianexpress.com/article/india/crime/india-other-asia-pacific-nations-civilisational-protectors-of-human-rights-says-president-8949182/

President Droupadi Murmu being felicitated by NHRC chairperson Justice Arun Kumar Mishra during the opening of a two-day conference in New Delhi on Wednesday. (PTI)

India, other Asia-Pacific nations civilisational protectors of human rights, says President

President Droupadi Murmu Wednesday said that India and other Asia-Pacific nations were civilisational protectors of human rights who could play a role in attaining a consensus on international issues.

Murmu was speaking after inaugurating the two-day conference organised the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan.

The conference of the National Human Rights Institutions (NHRIs) was organised in collaboration with the Asia Pacific Forum.

Murmu further mentioned India adopted a universal adult franchise right after gaining independence.

Among other speakers were NHRC chairperson Justice Arun Mishra, Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) secretary Amina Bouayach and Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions Chairperson Mr Doo-Hwan Song.

In the keynote address, Mishra spoke of the need for NHRIs of the Asia-Pacific to formulate a joint strategy to solve challenges in areas of climate change, child trafficking, Child Sexual Abuse Material (CSAM) and other crimes in cyberspace, the latest developments in Artificial Intelligence, among others.

He also spoke about the concentration of global wealth in a few hands.

Misra further pitched for a rights-based approach to be adopted in matters of essential health issues, and intellectual property rights. He also spoke about ensuring gender justice for women and LGBTQI community.

DAINIK JAGRAN, Prayagraj, 21.9.2023
Page No. 13, Size:(5.37)cms X (8.52)cms.

# महिला आरक्षण बिल लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी क्रांति : मुर्मु

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय में सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

राष्ट्रपति विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।

सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को इसी तरह का आरक्षण देने का प्रस्ताव अब ठोस रूप ले रहा है।' इस सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 सितंबर को एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लोगों से मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर नहीं देखने का आग्रह किया और पर्यावरण की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ● एएनआइ

देखभाल पर भी समान रूप से ध्यान देने को कहा। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि मनुष्यों की नासमझी से प्रकृति को गहरा नुकसान हुआ है। मुर्मु ने कहा, 'मनुष्य जितना अच्छा निर्माता है, उतना ही विध्वंसक भी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, यह पृथ्वी छठे विलुप्ति के चरण में प्रवेश कर चुकी है जिसमें अगर मानव निर्मित विनाश को नहीं रोका गया तो न सिर्फ मानव जाति का, बल्कि पृथ्वी पर अन्य जीवों का भी विनाश हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर न देखें।'

FINANCIAL EXPRESS, Delhi, 21.9.2023
Page No. 2, Size:(2.91)cms X (6.87)cms.

# PREZ: DON'T TREAT HUMAN RIGHTS ISSUE IN ISOLATION

PRESIDENT DROUPADI MURMU on Wednesday urged not to treat the human rights issue in isolation and sought "equal attention" to nursing the natural environment, lamenting that Mother Nature has been "deeply wounded" by human indiscretions.

FINANCIAL EXPRES
READ TO LEA

DAINIK JAGRAN, Kanpur, 21.9.2023
Page No. 15, Size:(5.37)cms X (8.51)cms.

# महिला आरक्षण बिल लैंगिक न्याय के लिए सबसे परिवर्तनकारी क्रांति : मुर्मु

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक लैंगिक न्याय के लिए हमारे समय में सबसे परिवर्तनकारी क्रांति होगी।

राष्ट्रपति विज्ञान भवन में एशिया प्रशांत के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के द्विवार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन करने के बाद सभा को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा, 'हमने स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया है।

सुखद संयोग है कि राज्य विधानसभाओं और संसद में महिलाओं को इसी तरह का आरक्षण देने का प्रस्ताव अब ठोस रूप ले रहा है।' इस सम्मेलन का आयोजन 20 और 21 सितंबर को एशिया प्रशांत फोरम के सहयोग से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कर रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने लोगों से मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर नहीं देखने का आग्रह किया और पर्यावरण की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ● एएनआइ

देखभाल पर भी समान रूप से ध्यान देने को कहा। उन्होंने इस बात पर अफसोस जताया कि मनुष्यों की नासमझी से प्रकृति को गहरा नुकसान हुआ है। मुर्मु ने कहा, 'मनुष्य जितना अच्छा निर्माता है, उतना ही विध्वंसक भी है। वैज्ञानिक अध्ययनों के मुताबिक, यह पृथ्वी छठे विलुप्ति के चरण में प्रवेश कर चुकी है जिसमें अगर मानव निर्मित विनाश को नहीं रोका गया तो न सिर्फ मानव जाति का, बल्कि पृथ्वी पर अन्य जीवों का भी विनाश हो जाएगा। इस संदर्भ में मैं आपसे आग्रह करती हूं कि आप मानवाधिकारों के मुद्दे को अलग रखकर न देखें।'

# Moral obligation of international community to ensure human rights: President Murmu

https://ddnews.gov.in/national/moral-obligation-international-community-ensure-human-rights-president-murmu

President Droupadi Murmu inaugurated Annual General Meeting and Biennial Conference of the Asia Pacific Forum on Human Rights in New Delhi on September 20, 2023.

Speaking on the occasion, the President emphasised that the Asia Pacific Region Forum has a great role to play in evolving an international consensus through deliberation and consultation with human rights institutions and stakeholders all over the world.

She urged all not to treat the issue of human rights in isolation and pay equal attention to nursing Mother Nature which is deeply wounded by the indiscretions of human beings. She said that in India, we believe that every particle of the universe is a manifestation of divinity. She said that we should rekindle our love for nature to conserve and enrich it before it is too late.

The President was happy to note that one session in the Conference is exclusively devoted to the topic of environment and climate change. She expressed confidence that the Conference would come out with a comprehensive declaration that would pave the way for betterment of humanity and the planet.

She said that our Constitution adopted universal adult franchise right, since the inception of the Republic, and enabled us to usher in numerous silent revolutions, in the field of gender justice, and protection of life and dignity.

She added that we ensured a minimum of 33 percent reservation for women in local bodies' elections and in a pleasant co-incidence, a proposal to provide similar reservation for women in the state assemblies and national Parliament.

# President Murmu Inaugurates Asia Pacific NHRI Conference in New Delhi

https://english.newstracklive.com/news/president-murmu-inaugurates-asia-pacific-nhri-conference-in-new-delhi-sc1-nu318-ta318-1298152-1.html

NEW DELHI: President Droupadi Murmu inaugurated the commencement of a two-day gathering for National Human Rights Institutions (NHRIs) across the Asia Pacific region. The event, organized in collaboration with the Asia Pacific Forum and hosted by India's National Human Rights Commission (NHRC), took place at Vigyan Bhawan in New Delhi.

During her address, President Murmu emphasized the historical commitment of India and other Asia Pacific nations to safeguarding human rights, underlining their potential to foster international consensus on related issues. She particularly drew attention to the critical impact of climate change on human rights, urging the audience to prioritize nature conservation before it becomes irreversible.

President Murmu proudly noted India's enduring commitment to democratic values and individual rights, highlighting its early adoption of universal adult franchise rights and the establishment of a minimum 33% reservation for women in local government bodies. She hinted at an upcoming proposal to extend this reservation to legislative assemblies and parliament.

In the keynote speech, Justice Arun Mishra, Chairperson of NHRC India, stressed the need for collaborative strategies among Asia Pacific NHRIs to address emerging challenges to human rights. These challenges encompassed areas such as climate change, child trafficking, Child Sexual Abuse Material (CSAM), cybercrime, the latest developments in Artificial Intelligence, and the growing global wealth disparity. Justice Mishra called for humane working conditions for all workers and urged businesses to take responsibility for waste management. He advocated for a right-based approach to intellectual property rights in essential health services and championed gender justice and opportunities for the differently-abled.

Amina Bouayach, Secretary of the Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), emphasized the crucial role of NHRIs in promoting and safeguarding human rights amidst contemporary challenges like poverty, discrimination, and shrinking civic space.

Doo-Hwan Song, Chairperson of the Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions, also addressed the attendees.

Before the official proceedings began, Bharat Lal, Secretary General of NHRC, provided an overview of the scheduled discussions during the two-day conference. He highlighted that the event commemorated the 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) and 30 years of National Human Rights Institutions and the Paris Principles, with a sub-theme centered on the environment and climate change.

The conference welcomed Heads, members, and senior officials of NHRIs from the Asia Pacific region, observer countries, representatives from Union and State governments, State Human Rights Commissions, Special Rapporteurs, Monitors, various institutions dedicated to human rights, civil society members, NGOs, human rights defenders, lawyers, jurists, academicians, diplomats, and representatives from international organizations and academic institutions.

In addition to the conference, NHRC is hosting an international seminar on 'Business and Human Rights' to develop strategies that prioritize human rights and environmental sustainability in business operations.

TIMES OF INDIA, Delhi, 21.9.2023
Page No. 20, Size:(17.96)cms X (3.31)cms.

# Put rights, nature on same pedestal: Prez

**New Delhi**: Human rights must not be seen in isolation and equal attention must be paid to nursing the environment, which has been "deeply wounded" by human indiscretion, President Droupadi Murmu said on Wednesday.

She was addressing the biennial of Asia Pacific region's national human rights institutions (NHRIs), hosted by the National Human Rights Commission, where she said love for nature should be rekindled to conserve and enrich it "before it is too late".

"Human beings are as good a creator as destroyer. According to scientific studies, this planet has entered the phase of sixth extinction where man-made destruction, if not stopped, will be the undoing of not only the human race but also the other lives on the earth... In this context, I would urge you to not to treat the issue of human rights in isolation and pay equal attention to nursing Mother Nature, which is deeply wounded by the indiscretions of human beings," she said. Emphasising that the Indian ethos is to believe there is divinity in every particle of the universe also said people must ponder over the causes of the pandemic and natural disasters that have been taking place all around. "Let us also ponder over the challenges of climate change that have been threatening the very existence of the planet," she said.

President Murmu also underlined that India and Asia Pacific nations are protectors of human rights . TNN

TIMES OF INDIA, Chandigarh, 21.9.2023
Page No. 12, Size:(7.46)cms X (19.67)cms.

# Put rights, nature on same pedestal: Prez

**New Delhi**: Human rights must not be seen in isolation and equal attention must be paid to nursing the environment, which has been "deeply wounded" by human indiscretion, President Droupadi Murmu said on Wednesday.

She was addressing the biennial of Asia Pacific region's national human rights institutions (NHRIs), hosted by the National Human Rights Commission.

"Human beings are as good a creator as destroyer. According to scientific studies, this planet has entered the phase of sixth extinction where man-made destruction, if not stopped, will be the undoing of not only the human race but also the other lives on the earth... In this context, I would urge you to not to treat the issue of human rights in isolation and pay equal attention to nursing Mother Nature, which is deeply wounded by the indiscretions of human beings," she said. TNN

# Bahanaga train tragedy: NHRC warns Odisha Chief Secy, IRB Chairman

https://www.orissapost.com/bahanaga-train-tragedy-nhrc-warns-odisha-chief-secy-irb-chairman/

Kendrapara: The National Human Rights Commission (NHRC) has warned the Chief Secretary (CS) of Odisha and the Indian Railway Board (IRB) Chairman to invoke its coercive power u/s 13 of the PHR Act, 1993 calling for their personal appearances before the Commission in connection with the Bahanaga train tragedy report.

The action will be taken if they fail to submit the requisite report related to the accident within a period of four weeks.

The NHRC passed the order last week on a petition filed by human rights activist Radhakanta Tripathy.

Tripathy in his petition stated that the rare and tragic train accident happened in Bahanaga Bazaar station in Balasore June 2 due to gross negligence of the Railways.

There have been subsequent violations of human rights of the passengers, both dead and alive, due to a lack of appropriate and timely action by the Railways and State administration, he alleged.

Tripathy said that the rights of deceased/ victims are being violated by the state Government/Railways as the authorities have failed to preserve the bodies till identification of the same by their kin.

He said dead bodies are still lying for disposal and fake claimants are coming forward to stake claims for which the compensation cases to the next of kin of the deceased victims are pending.

The petitioner requested the NHRC for an in-depth analysis, independent and impartial investigation of the incident and sought for heavy compensation to the family members of the deceased, dignified farewell of the dead bodies and compensation with proper medical care to the injured ones.

He also sought for intervention of the administration and Railways for proper documentation of all the passengers for loss of documents and preparation of further documents for claiming insurance and service benefits, Students, children care etc.

Earlier the NHRC had sought Action Taken Reports from the Odisha CS and the IRB Chairman, within a period of four weeks.

However, despite direction, neither the CS nor the Chairman submitted any report till date.

INDIAN EXPRESS, Mumbai, 21.9.2023
Page No. 10, Size:(5.34)cms X (13.68)cms.

# India, other Asia-Pacific nations civilisational protectors of human rights, says President

**President Droupadi Murmu being felicitated by NHRC chairperson Justice Arun Kumar Mishra during the opening of a two-day conference in New Delhi on Wednesday.** *PTI*

**EXPRESS NEWS SERVICE**
NEW DELHI, SEPTEMBER 20

PRESIDENT DROUPADI Murmu Wednesday said that India and other Asia-Pacific nations were civilisational protectors of human rights who could play a role in attaining a consensus on international issues.

Murmu was speaking after inaugurating the two-day conference organised the National Human Rights Commission (NHRC) at Vigyan Bhawan.

The conference of the National Human Rights Institutions (NHRIs) was organised in collaboration with the Asia Pacific Forum.

Murmu further mentioned India adopted a universal adult franchise right after gaining independence.

Among other speakers were NHRC chairperson Justice Arun Mishra, Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) secretary Amina Bouayach and Asia Pacific Forum of National Human Rights Institutions Chairperson Mr Doo-Hwan Song.

In the keynote address, Mishra spoke of the need for NHRIs of the Asia-Pacific to formulate a joint strategy to solve challenges in areas of climate change, child trafficking, Child Sexual Abuse Material (CSAM) and other crimes in cyberspace, the latest developments in Artificial Intelligence, among others.

He also spoke about the concentration of global wealth in a few hands.

Misra further pitched for a rights-based approach to be adopted in matters of essential health issues, and intellectual property rights. He also spoke about ensuring gender justice for women and LGBTQI community.

On the other hand, Bouayach said NHRIs were critical for promoting and protecting human rights in challenging times of poverty, discrimination and shrinking civic space.

# NHRC Chairperson Justice Arun Mishra stresses on need-based distributive justice, says no one should be deprived of rights due to socio-economic conditions

https://www.indialegallive.com/top-news-of-the-day/news/nhrc-chairperson-justice-arun-mishra-need-based-distributive-justice/

Chairperson of National human Rights Commission (NHRC), Justice Arun Mishra on Wednesday stressed on ensuring need-based distributive justice for people, pointing out that no one should be deprived of rights due to socio-economic conditions and personal beliefs.

Speaking during the 28th Annual General Meeting (AGM) and biennial conference of Asia Pacific Forum at the Plenary Hall of Vigyan Bhawan, New Delhi, the NHRC Chairperson said the concentration of wealth in a few hands globally was causing a brooding sense of injustice.

He said there was an acute need for the inclusion of marginalised and other disadvantaged segments of society in the gains of globalisation and that inequality in income and wealth was attributed mainly to hi-tech aggregation platforms.

Most of them were not producers of the goods, but mere distributors. Their monopoly was disrupting the global supply chain and posed challenges to the producers and distributors, apart from small and medium retailers worldwide. They were also involved in unfair labour practices violating human rights, he added.

As per Justice Mishra, India had a history of more than 5000 years, comprising ethos, compassion, empathy and human dignity as its core values. He said inspired by the culture and ethos of the country, the Constitution makers incorporated these values in the Constitution of India.

In the same spirit, India pioneered the establishment of the National Human Rights Commission as a statutory body in 1993. The motto of the Commission was ‘Sarve Bhavantu Sukhinah,’ which meant let everybody be happy, he added.

Noting that human rights were moral, pre-legal rights, which could neither be granted nor taken away, the NHRC Chairperson said that every law was required to be compliant with human rights.

He said the Commission was committed to upholding the dignity and rights of every human in the vast Asia-Pacific region with diverse cultures, languages, traditions and religions. NHRC was entrusted with the noble task of upholding the human rights of those who could not fight for their rights, he added.

Talking about the challenges of disparities, which persisted in the society and the injustices that continued to afflict the people in many ways, Justice Mishra said everyone cherished the value of equality, freedom and justice.

In that spirit, it was important to protect human rights as well as provide expeditious and speedy machinery for the redressal of grievances.

He said the big businesses involved in hazardous business activity need to be accountable for human rights. After the worst gas tragedy in Bhopal in 1984, the hazardous debris still awaited removal. The delay was causing contamination of groundwater and soil. Business houses must be responsible for processing waste and removing debris from their premises. Stringent safety measures and liability were necessary to prevent the recurrence of such incidents, he added.

The right of freedom of profession, business, trade and occupation, including the right to property and intellectual property, are to be respected. However, they are subject to limitations and restrictions in the public interest. The intervention of regulatory bodies, particularly in pricing life-saving drugs, medicines, vaccines and medical devices, is necessary for protecting the right to health, which is part of the right to life.

Consumers were to be protected against unrealistic price extraction. Every packed product should reflect MRP. Pricing must co-relate with the cost of production, which consumers must know.

The right to livelihood is part of the right to life. We must ensure that workers involved in various economic activities are provided humane working conditions. For the tribals who live in remote and forest areas, their customary rights must be respected. Unfair trade practices, too, violate human rights. Overuse of fertilisers and impermissible pesticides damages soil, water and health and creates intergenerational issues.

In every country, to improve the quality of life of their citizens, the governments are pursuing wealth creation in economic activities. However, we must ensure that we do not cause permanent damage to the environment, nature, water bodies, flora and fauna. Our moral duty is to ensure that future generations do not pay the price for our actions or omissions.

He said humans were already paying the price due to environmental damage and climate change. Unfortunately, nature’s fury always impacts the weakest. Today, erratic rainfall, prolonged drought leading to forest fires, and high-intensity cyclones are playing havoc with lives and livelihoods.

Water and air pollution must be addressed. Prevention of deforestation and increasing forest cover are necessary for the survival of mankind. The comity of nations came together and decided to improve the quality of people’s lives by agreeing to Sustainable Development Goals, which are to be achieved by 2030.

He stressed on practising the culture of “recycle, reuse and reduce” for inter-generational equity.

Noting that the proliferation of cyberspace has created challenges for human rights, like hacking, dark web, fraud, and human trafficking, Justice Mishra said the children have become more vulnerable to such threats, citing the example of Child Sexual Abuse Material (CSAM).

He said the NHRC India recently held a conference on the issue of CSAM stressing on evolving better mechanisms to monitor and combat the misuse of cyberspace.

Blocking CSAM and malicious content required the big players on the internet to be sensitive and proactive in protecting the human rights of marginalised sections by identifying and taking down offensive content, he added.

Earlier, President Droupadi Murmu inaugurated the two-day conference of National Human Rights Institutions of the Asia Pacific Region at the Plenary Hall of Vigyan Bhawan, New Delhi.

The inaugural session of the National Human Rights Institutions of the Asia Pacific Region conference kickstarted at 11:00 am with the Annual General Meeting (AGM), 2023.

At 12:30, a seminar was held by NHRC, India on ‘Business and Human Rights’. The seminar was divided into two thematic sessions – ‘Harmonising climate change, human rights and business,’ and ‘Advancing human rights in business and industry.’

A Biennial Conference will be held tomorrow as part of the event, to celebrate the 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR) and 30 years of National Human Rights Institutions and the Paris Principles, with a sub-theme on the environment and climate change.

# Arunachal: Lokhi Wangsu death case, NEHRO files Complaint with NHRC

Lokhi Wangsu was a disciplined youth residing in Village Naitong in Tirap district of Arunachal Pradesh.

https://arunachal24.in/arunachal-lokhi-wangsu-death-case-nehro-files-complaint-with-nhrc/

KHONSA- The North East Human Rights Organisation (NEHRO) filed a complaint with the National Human Rights Commission (NHRC) on 19 September, alleging misuse of power and unwarranted use of force by the Assam forest battalion of Dibrugarh District, resulting in the tragic death of Lokhi Wangsu, who was a disciplined youth residing in Village Naitong in Tirap district of Arunachal Pradesh.

In his complaint NEHRO secretary Buteng Tayeng stated that on the morning of 18th September 2023, at approximately 7.30 a.m., Lokhi Wangsu was fatally shot by members of the Assam Forest Battalion at Hukanjuri Range Forest, Dibrugarh District, Assam.

Arunachal: West Siang Police arrests two drug peddlers

Tayeng further stated that " The actions of the Assam Forest Battalion raise serious concerns about the excessive use of force and a potential violation of human rights, especially considering the victim's peaceful intent in searching for his lost domestic cow within the r4esevre forest area.

Tayeng urged the NHRC to conduct a thorough and impartial investigation into this matter, holding the responsible parties accountable for their actions.

The body of a 24-year-old Lokhi Wangsu, was found near the forested area of Hukanjuri near the Arunachal-Assam boundary on Monday. The youth's body had marks of bullet injuries.

The locals have alleged that the youth died after personnel of the forest battalion of Assam's Dibrugarh district fired at him while he was looking for his missing cow within the reserved forest area in the morning of 18 September.

Meanwhile, the victim's relatives have filed an FIR with both the Arunachal and the Assam Police, as the incident occurred near the reserved forest area which falls under the jurisdiction of Assam.

TIMES OF INDIA, Mumbai, 21.9.2023
Page No. 23, Size:(2.66)cms X (4.75)cms.

# Murmu bats for environment

Human rights must not be seen in isolation and equal attention must be paid to nursing the environment, which has been "deeply wounded" by human indiscretion, President Droupadi Murmu said on Wednesday. TNN

# Women's reservation bill most transformative revolution in our times for gender justice: Prez

https://kashmirreader.com/2023/09/20/womens-reservation-bill-most-transformative-revolution-in-our-times-for-gender-justice-prez/

New Delhi: A day after the government introduced a bill to provide 33 per cent reservation to women in the Lok Sabha and state assemblies, President Droupadi Murmu on Wednesday said it will be the most "transformative revolution in our times" for gender justice.

Murmu was addressing a gathering after inaugurating the biennial conference of the national human rights institutions (NHRIs) of Asia Pacific held at the Vigyan Bhawan here.

The women's reservation bill was the first bill to be introduced in the new Parliament building on Tuesday.

"We have ensured a minimum of 33 per cent reservation for women in local bodies' election… In a more pleasant coincidence, a proposal to provide a similar reservation for women in state assemblies and national Parliament is taking shape now. It will be the most transformative revolution in our times for gender justice," the President said.

The event is being organised by the National Human Rights Commission (NHRC) in collaboration with the Asia Pacific Forum (APF) from September 20-21.

Amina Bouayach, secretary of Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), and Doo-Hwan Song, chairperson, APF, and NHRC chairperson justice (retd) Arun Kumar Mishra were also present on the occasion.

The APF will also hold its 28th Annual General Meeting (AGM) on Wednesday to discuss the issues of common interest to member countries. In the conference, more than 1,300 delegates from India and abroad are likely to participate, the NHRC earlier said.

The conference is being attended by heads, members and senior officials of the NHRIs of various countries, along with representatives from the Union and state governments, state human rights commissions, special rapporteurs, monitors and various institutions involved in the protection and promotion of human rights in the country.

PTI

HITAVADA, Nagpur, 21.9.2023
Page No. 10, Size:(18.31)cms X (11.68)cms.

# Don't treat human rights issue in isolation, pay equal attention to nature: President

■ **Delhi Bureau & Agencies**
NEW DELHI, Sept 20

PRESIDENT Droupadi Murmu on Wednesday urged not to treat the human rights issue in isolation and sought "equal attention" to nursing the natural environment, lamenting that Mother Nature has been "deeply wounded" by human indiscretions.

Addressing a gathering at the biennial conference of national human rights institutions of the Asia Pacific at Vigyan Bhawan, she also said the love for nature should be rekindled to conserve and enrich it "before it is too late".

The event is being organised by the National Human Rights Commission (NHRC), India, in collaboration with the Asia Pacific Forum (APF) from September 20-21. Murmu said she looked at the list of conferences the forum previously held and expressed her happiness that this is the first in-person sitting in the post-COVID phase. "I am told that the conference is being attended by nearly 100 foreign delegates," she said. Murmu also underlined the degradation the natural environment is facing.

"Human beings are as good a creator as a destroyer. According to scientific studies, this planet has entered the phase of sixth extinction where man-made destruction, if not stopped, will be the undoing of not only the human race but also the other lives on the earth," Murmu said. "In this context, I would urge you to not to treat the issue of human rights in isolation and pay equal attention to nursing Mother Nature, which is deeply wounded by the indiscretions of human beings," she added. In India, the President added, "We believe that every particle of the universe is a manifestation of divinity. Let us rekindle our love for nature to conserve and enrich it before it is too late."

# ‘Most transformative revolution’: President Murmu hails women’s reservation bill

President Daroupadi Murmu was addressing a gathering after inaugurating the biennial conference of the national human rights institutions (NHRIs) of Asia Pacific held at the Vigyan Bhawan in New Delhi

https://www.hindustantimes.com/india-news/most-transformative-revolution-president-murmu-hails-women-s-reservation-bill-101695211701125.html

President Droupadi Murmu on Wednesday hailed the newly introduced Women’s Reservation Bill and said that it “would be the most transformative revolution in our times for gender justice”.

“We have ensured a minimum of 33% reservation for women in local bodies elections. What is more, in a pleasant coincidence, a proposal to provide similar reservations for women in the state assemblies and national Parliament is taking shape now. It will be the most transformative revolution, in our times for gender justice,’’ said Murmu.

The government on Tuesday introduced a bill in the Parliament which proposes to reserve a third of seats or 33% in the Lower House and state assemblies for women.

On Wednesday, Union law minister Arjun Ram Meghwal moved the Constitution (128th Amendment) Bill 2023, to be taken up for consideration.

The Women’s Reservation Bill was the first bill to be introduced in the new Parliament building on Tuesday and the debate started in Lok Sabha on Wednesday.

Most of the opposition parties, including Congress, extended support to the bill but questioned the delay in implementation.

Former Congress president Sonia Gandhi demanded that the women’s reservation bill must be implemented immediately, while pitching for OBC quota within reserved seats as she declared her party’s support for the bill.

Murmu was addressing a gathering after inaugurating the biennial conference of the national human rights institutions (NHRIs) of Asia Pacific held at the Vigyan Bhawan in New Delhi.

Discussing India’s achievements in promoting human rights, Murmu highlighted the country’s commitment to universal adult franchise from the Republic’s inception.

“Our Constitution adopted universal adult franchise right, since the inception of the Republic, and enabled us to usher in numerous silent revolutions, in the field of gender justice, and protection of life and dignity.”

Praising the government and the various schemes launched by Prime Minister Narendra Modi, she said, “Over the years, the government has launched several ambitious schemes to ensure basic facilities like housing, toilets, education, and health facilities and thus protect the dignity of the poor. I come from a background where I know how privation, poverty, and illiteracy make life miserable, with economic and social disparities which are no less violative of human rights as any other form of discrimination.”

Murmu inaugurated the annual general meeting and Biennial Conference of the Asia Pacific Forum on Human Rights in New Delhi celebrating the landmark 75th anniversary of the Universal Declaration on Human Rights (UDHR). during which she urged all not to treat the issue of human rights in isolation and pay equal attention to nursing Mother Nature which is deeply wounded by the indiscretions of human beings.

The theme of the seminar revolved around, ‘Harmonising climate change, human rights, and business ‘and ‘Advancing human rights in business and industry.’

The NHRC is a statutory body, constituted on 12 October 1993, under the Protection of Human Rights Ordinance. It is responsible for the protection and promotion of human rights as defined by the act as ‘rights relating to life, liberty, equality and dignity of the individual’ guaranteed by the Constitution.

NHRC submits an annual report to the president every year which is then presented in both the Rajya Sabha and the Lok Sabha.

Last year, the theme of the seminar was, ‘Human Rights in Indian Culture and Philosophy’ in collaboration with Indira Gandhi National Centre for Art.

Human beings are as good a creator as a destroyer. According to scientific studies, this planet has entered the phase of sixth extinction where man-made destruction, if not stopped, will be the undoing of not only the human race but also the other lives on the earth

**DROUPADI MURMU** | PRESIDENT OF INDIA